हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस के स्थापन दिवस समारोह में कहा कि दो वर्ष में अपराधों में 18.77 प्रतिशत कमी आई है

जयपुर,16अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कम्यूनिटी पुलिसिंग से साइबर अपराध, नशा व संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इनसे निपटने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया और परेड ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया।

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने 77 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसालें पेश की हैं। शर्मा ने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों ने आमजन की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग से साइबर अपराध, नशा व संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26, लूट में 50.75 तथा महिला अत्याचारों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड में आयोजित सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बीजू जॉर्ज जोसफ व बिपिन कुमार पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार, उपनिरीक्षक सीताराम भाकल व गिरधारी लाल शर्मा तथा सहायक उपनिरीक्षक गोविंदराम को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से पुरस्कृत किया। इस दौरान शर्मा ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए नया पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे पहले उन्होंने परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस कार्मिकों के स्पोर्ट्स, वेलफेयर एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों के निर्माण की भी घोषणा की।

प्र.मंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने फोन पर बात की

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। पश्चिम एशिया में बढ़ ते तनाव के बीच भारत और फ्रांस ने एक बार फिर दुनिया को अपनी रणनीतिक साझेदारी का अहसास कराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने करीबी मित्र इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात की। इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु न केवल क्षेत्रीय शांति रही, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल किया जाना अनिवार्य है। दरअसल, यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है और यहां किसी भी तरह का अवरोध दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है।

'अमेरिका की छूट खत्म होने के बाद भी रुस से तेल खरीदते रहेंगे'

भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील से पहले बड़ा ऐलान किया

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। पहले पश्चिम एशिया में संघर्ष, फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी और अब अमेरिका द्वारा रूस और ईरान से तेल खरीदने की अस्थायी छूट समाप्त कर दिए जाने के बाद भी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेगा।

- **सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा रुस से तेल खरीदने के कारण ही भारत के पास 60 दिनों का तेल भंडार है।**

सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, यह खरीदारी राष्ट्रीय हित की मांग है और पहले भी ऐसी स्थिति में भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया था। अभी भी वॉशिंगटन को मनाने की कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी तेल-एलपीजी आयात बढ़ाने और रूसी तेल की निरंतर आपूर्ति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके ठीक कुछ दिन पहले, विदेश सचिव विक्रम मिसरी की हालिया वॉशिंगटन यात्रा के दौरान भी इन मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ था, जहां मिसरी ने अमेरिका-भारत ऊर्जा साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया।

अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मौजूदा पश्चिम एशिया संकट में भारत की कच्चे तेल की विशाल जरूरत को रूस के अलावा अभी और कोई देश पूरा नहीं कर सकता। एक अधिकारी के मुताबिक, ईरान पर हमले की शुरुआत से पहले तक भारत अपनी जरूरत का 60 फीसद तक क्रूड होर्मुज जल मार्ग के रास्ते ला रहा था।

अब यह रास्ता बंद है। इराक व कुवैत से आपूर्ति एकदम ठप है। यूएई व सउदी अरब से आपूर्ति सीमित हो चुकी है। इन देशों से आपूर्ति कब सामान्य होगी, यह अनिश्चित बना हुआ है। रूस से भारी पैमाने पर आयात करने की वजह से ही भारत के पास अभी भी 60 दिनों का पेट्रोलियम भंडार है।

ऐसे में रूस से तेल खरीद पर रोक लगाना भारत के लिये संभव नहीं है। रूस से तेल खरीदने का कोई सरकारी डाटा तो नहीं हैं लेकिन निजी एजेंसी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि रूसी कच्चे तेल का आयात मार्च, 2026 में दोगुना होकर 2.06 मिलियन बैरल प्रति दिन पहुंच गया है, जबकि फरवरी 1.06 मिलियन बैरल रोजाना की खरीद हुई थी।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को कांग्रेस ने सस्पैंड किया

- **कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह ने कहा इन विधायकों ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा था**
- **इससे पूर्व इन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर निलम्बन की कार्यवाही की गई।**

चंडीगढ़ , 16 अप्रैल। हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों को पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर 'क्रॉस-वोटिंग' करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह ने कहा कि संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन का गंभीर संज्ञान लेते हुए पार्टी ने पांच विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य अनुशासन समिति की सिफारिश और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद यह कार्रवाई की गई है।

कांग्रेस ने नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी , साढ़ौरा विधायक रेणु बाला , पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास , हथीन सीट से विधायक मोहम्मद इसराइल और रतिया से विधायक जरनैल सिंह पर पार्टी की आधिकारिक लाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति (डीएसी) ने हाल ही में पांच विधायकों के निलंबन की सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने पूर्व में कहा था कि समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में पांच पार्टी विधायकों की ओर से कथित 'क्रॉस-वोटिंग' के मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व को अपना निर्णय बता दिया है। समिति ने विधायकों को निलंबित करने की सिफारिश की थी। डीएसी ने विधायकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों के जवाबों की जांच की।

इससे पहले, कांग्रेस ने हरियाणा के अपने पांच विधायकों को 'क्रॉस-वोटिंग' के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में जानबूझकर मतदान न करके दल-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

रूस और ईरान से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बुधवार को पत्रकारों से कहा, "हम रूसी तेल पर सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेंगे, और न ही ईरानी तेल पर। यह वह तेल था, जो 11 मार्च से पहले समुद्र में था, इसलिए वह सब उपयोग में आ चुका है।"

ये अस्थायी छूटें बढ़ती ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में दी गई थीं, जिनके तहत निर्धारित समय सीमा से पहले जहाजों पर लोड किए गए तेल के सीमित लेन-देन को वैश्विक बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी गई, ताकि युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम किया जा सके।

इन छूटों को न बढ़ाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब वॉशिंगटन, ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति को और मजबूत कर रहा है।

रूसी तेल की खरीद पर दी गई छूटों ने भारत को वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति सुरक्षित करने में मदद की। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों ने इस अवधि में लगभग 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर दिए।

रिलायंस सहित, प्रमुख रिफाइनरियों ने इस वर्ष जनवरी में अमेरिकी दबाव के कारण रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों से खरीद कम कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए फिर से रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी।

चीन व ईरान के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की

बीजिंग/तेहरान, 16 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच चीन और ईरान के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जारी संघर्ष, युद्धविराम और शांति वार्ताओं पर विस्तार से चर्चा की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि संघर्ष विराम और संवाद की प्रक्रिया को बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही ईरानी जनता के मूल हितों के अनुरूप है और क्षेत्रीय व वैश्विक समुदाय की साझा अपेक्षाओं को भी दर्शाता है।

पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल पर लगी रोक को हटाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है।

- **खेड़ा ने याचिका दायर कर मांग की है कि ट्रांजिट बेल पर लगी रोक हटाई जाए।**

दरअसल, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। इसी के मद्देनजर पवन खेड़ा ने शीर्ष अदालत से राहत की गुहार लगाई है और अपने खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को ही पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया था और उनसे तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था। हालांकि, अब खेड़ा ने उसी आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगाई गई थी।

दिल्ली एयरपोर्ट पर दो विमानों के विंग्स टकराए

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर मंगलवार को बड़ा विमान हादसा टल गया, जब दो अलग-अलग एयरलाइंस के विमानों के विंग आपस में टकरा गए। घटना के बाद दोनों विमानों को तत्काल ग्राउंड कर दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी यात्री या क्रू सदस्य घायल नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार, आकासा एयर की फ्लाइट क्यूपी-1406 दिल्ली से हैदराबाद जाने के लिए तैयार थी और पुशबैक के बाद एप्रन पर खड़ी थी।

प्र.मंत्री मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और इस कोटा के लागू होने से न तो पुरुषों को और न ही किसी राज्य को कोई नुकसान होगा।

लोकसभा में महिला कोटा कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग के गठन से जुड़े तीन विधेयकों पर अपने प्रारंभिक वक्तव्य में मेघवाल ने कहा कि 815 में से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना 33 प्रतिशत आरक्षण का सरल सूत्र है।

प्रस्तावित कानूनों के अनुसार, लोकसभा की वर्तमान संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मेघवाल ने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के कोटे के भीतर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा।

मंत्री ने कहा कि यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रहता है, तो 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संभव नहीं होगा, क्योंकि यह 2026 के बाद उपलब्ध होने वाली जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा। इसी कारण संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है।

'मतदान से दो दिन पहले भी मिली क्लीन चिट तो दे पाएंगे वोट'

सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ी घोषणा की

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव से ठीक पहले तक अपीलीय ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा।

- **प.बंगाल की मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया व लोगों से कहा कि मताधिकार की प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करें।**

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा चुनाव से दो दिन पहले तक मंजूर किए जाएंगे, उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 21 अप्रैल या 27 अप्रैल 2026 तक अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए एक पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए, ताकि योग्य नागरिकों को मतदान से वंचित न होना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की अपील लंबित है, उन्हें केवल इसी आधार पर मतदान का अधिकार वापस नहीं दिया जाएगा, यानी अपील प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई यह पूरी जांच प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण रही है, जिसे कम समय में पूरा करना वास्तविक रूप से कठिन कार्य था। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अपीलीय स्तर पर आपत्तियों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने अधिकारों की पुन: प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करना चाहिए।

तृणमूल विधायक अब्दुर रज़ाक ने पार्टी छोड़ी

मुर्शिदाबाद, 16 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से केवल सात दिन पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुर्शिदाबाद जिले की जालंगी विधानसभा सीट से वरिष्ठ विधायक अब्दुर रज्जाक मंडल ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले से चुनावी माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है। रज्जाक मंडल लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे और स्थानीय स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।

अब्दुर रज्जाक मंडल ने जालंगी के कांटाबाड़ी स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने एलान किया वे अब टीएमसी के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने रानीनगर से टीएमसी उम्मीदवार सौमिक हुसैन पर निशाना साधा।

इज़रायल व लेबनान में दस दिन का सीज़फायर

34 सालों में पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है

वॉशिंगटन, 16 अप्रैल। पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक पहल सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इज़रायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर पर सहमति बन गई है।

- **इस बैठक की मेजबानी अमेरिका ने की है। ट्रंप ने इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया व कहा कि हम इस सीज़फायर को स्थाई शांति में बदलना चाहते हैं।**

डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरी अभी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने शांति की दिशा में कदम बढ़ ते हुए सीज़फायर पर सहमति जताई। यह अस्थायी सीज़फायर शाम 5 बजे ईस्टर्न टाइम (भारत में 17 अप्रैल की सुबह 2:30 बजे) से लागू होगा। उन्होंने कहा दुनिया भर में नौ युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और यह मेरा 10 वां लक्ष्य होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। बताया जा रहा है कि लेबनान की ओर से यह साफ संदेश दिया गया था कि जब तक जमीनी स्तर पर संघर्ष विराम लागू नहीं होता, तब तक किसी भी तरह की सीधी बातचीत संभव नहीं है। इस रुख के बाद कूटनीतिक प्रयास तेज हुए और अंतत: दोनों देशों ने सीजफायर पर सहमति जताई। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 वर्षों में पहली बार वॉशिंगटन डीसी में आमने-सामने मिले। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो भी मौजूद रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अस्थायी सीज़फायर को स्थायी शांति में बदलने के लिए दोनों देशों के साथ काम करें। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने इज़रायल और लेबनान के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की, जो 1993 के बाद पहली उच्च-स्तरीय पहल थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस बैठक में प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने, युद्धविराम लागू करने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और व्यापक शांति ढांचे की दिशा में आगे बढ़ ने पर सहमति बनी।

सरकार अभी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार मतदान के लिए जोर देकर यह नैरेटिव बनाना चाहती है कि कांग्रेस और विपक्ष महिला विरोधी हैं, या फिर वह विधेयक वापस ले लेगी? संभावना यही है कि सरकार मतदान करवाने पर जोर देगी, भले ही उसे सदन में हार का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन कुछ विपक्षी दलों को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रयास ज्यादा सफल होते नहीं दिख रहे हैं।

नीतीश के उदाहरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को कमज़ोर करने या तोड़ने के लिए "यूज़ एंड थ्रो" की नीति अपनाती है। इसके उदाहरण के रूप में शिवसेना, असम गण परिषद, शिरोमणि अकाली दल, एआईएडीएमके, एलजेपी, इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी जैसे दलों के विभाजन या कमज़ोर होने का हवाला दिया जाता है।

करीब 76 वर्ष के नायडू को आशंका है कि यदि स्पष्ट उत्तराधिकार योजना नहीं बनाई गई, तो टीडीपी का भी यही हाल हो सकता है। बिहार की घटनाओं की पृष्ठभूमि में, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से धीरे-धीरे अलग करना शुरू कर दिया है। साथ ही, नारा लोकेश के करीबी सहयोगियों को भी अहम पद दिए गए हैं। किलारू राजेश को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और सना सतीश को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

नायडू ने पार्टी के पोलित ब्यूरो, राष्ट्रीय और राज्य समितियों में बड़े बदलाव किए हैं, जिनके तहत, कई वरिष्ठ नेताओं को प्रतीकात्मक भूमिकाओं में सीमित कर दिया गया है। सोमि रेड्डी, चंद्र मोहन रेड्डी, बोंडा उमामहेश्वर राव, कन्ना लक्ष्मी नारायण, कला वेंकट राव और कूना रवि कुमार जैसे नेताओं को कम प्रभाव वाले पद दिए गए हैं।

नायडू के ये कदम नीतीश कुमार प्रकरण के असर के रूप में देखे जा सकते हैं। साथ ही, इसे भाजपा के विस्तारवादी रुख को लेकर उनकी आशंकाओं से भी जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे भी, वे ही क्षेत्रीय दल टिके रहे और प्रासंगिक बने रहे हैं, जिन्होंने समय रहते उत्तराधिकार की योजना तय कर ली, जैसे बिहार में आरजेडी, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तेलंगाना में बीआरएस और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी। वहीं, बीएसपी और बीजेडी जैसे दलों ने अभी तक स्पष्ट उत्तराधिकार योजना नहीं बनाई है।

महिला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हैं और उन्हें उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि महिला आरक्षण विधेयक को नई जनगणना के साथ क्यों नहीं लाया जा रहा, जो ओबीसी की सही तस्वीर पेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस और भाजपा जाति जनगणना के नए आंकड़ों से डर रहे हैं, जो ओबीसी के लिये उनका सही हिस्सा सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है, लेकिन इसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों के आंकड़े शामिल नहीं हैं, और यह ईमानदारी नहीं है।

एक तरफ ट्रंप वार्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समझौते के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ईरान अपने अनुसार यूरेनियम संवर्धन करने के अधिकार पर अड़ा हुआ है। अमेरिका ने अपने प्रस्ताव में 20 वर्षों तक ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन न करने की बात कही थी।

ईरान ने सुझाव दिया है कि वह केवल पाँच वर्षों तक संवर्धन कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हो सकता है।

इसके अलावा, संवर्धन की सीमा पर भी सहमति नहीं बन पाई है। पहले एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत ईरान को 3.67 प्रतिशत तक संवर्धन की अनुमति थी। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के पास पहले से ही 60 प्रतिशत से अधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार है।

अपने आक्रामक रुख का विस्तार करते हुए, हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका एक ओर स्ट्रेट की सैन्य नाकाबंदी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर "ऑपरेशन फ्यूरी" नामक एक नया आर्थिक अभियान भी चला रहा है, जो सैन्य विकल्प का आर्थिक स्वरुप है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट अब ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए एक व्यापक आर्थिक युद्ध कार्यक्रम को औपचारिक रूप दे रहे हैं।

ईरान पहले से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति में है, उसके प्रमुख उद्योग प्रभावित हैं, व्यापार घट चुका है और तेल राजस्व में भारी कमी आई है। इसके बावजूद, ईरान ने अपने लोगों की कठिनाइयों के बीच भी संघर्ष जारी रखा है।

अमेरिका की रणनीति अब यह है कि आंतरिक आर्थिक दबाव बढ़ाकर देश में विरोध और असंतोष को उकसाया जाए, जिससे शासन पर दबाव बने। हालांकि, यह एक पश्चिमी दृष्टिकोण है, और ईरान ने कई बार दिखाया है कि वह इस तरह के दबाव के आगे आसानी से नहीं झुकता।

राज्यसभा के निर्विरोध उपसभापति बनेंगे हरिवंश

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने निर्वाचन प्रक्रिया से विपक्ष के अलग रहने की घोषणा की

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। राष्ट्रपति की ओर से नामित हरिवंश ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय में उपसभापति पद के लिए नामांकन किया। वे जनता दल (यू) से सदन में दो बार निर्वाचित एवं दोनों बार राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं।

- **वरिष्ठ जद यू नेता तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बनेंगे।**

राज्यसभा में कल उपसभापति का निर्वाचन होगा। विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर आपत्ति जाहिर करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया से दूरी बनाने का फैसला किया है। इसका अर्थ है कि बिना विरोध हरिवंश फिर से उपसभापति बन जायेंगे।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि विपक्ष ने कल निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। हालांकि इसके पीछे हरिवंश का निरादर करने का कोई ईरादा नहीं है। विपक्ष को उम्मीद है कि हरिवंश अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष के अनुरोधों के प्रति अधिक सहिष्णु और ग्रहणशील होंगे। जयराम रमेश ने तीन आपत्तियां जताई हैं। उनका कहना है कि 7 सालों से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है। राज्यसभा में राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किसी व्यक्ति पर इससे पहले कभी भी उपसभापति पद के लिए विचार नहीं किया गया है। वहीं, उन्हें तीसरी बार मौका देते समय विपक्ष से विचार विमर्श भी नहीं किया गया। पिछले माह राष्ट्रपति ने हरिवंश को राज्यसभा का सदस्य नामित किया था। हरिवंश नारायण सिंह का 9 अप्रैल को उपसभापति के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया। तब से यह पद खाली है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन का संचालन करते हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908